



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11508

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 876 वर्ष 2026

कमला कांत नायक

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मनोज कुमार साहू, श्री निवास यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

मैं परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करता/करती हूँ, जिसमें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), झांसी को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 05.12.2024 को दायर बहाली आवेदन पर सुनवाई करें और याचिका संख्या 3786/2024 (डी202406370003786 दमारू लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 12.11.2024 को पारित आदेश को वापस लेने के लिए शीघ्रता से और कम समय में निर्णय लें।

3. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मामला लंबे समय से लंबित है। उनका तर्क है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मुकदमे का निर्णय कानून के अनुसार शीघ्रता से और अधिमानतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर करे, लेकिन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

16 जनवरी, 2026/ ऐमन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"